nt>

Title: Need to provide financial assistance to State Government of Himachal Pradesh for better educational facilities in the State .-Laid.

श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक पाठशाला से लेकर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवम् कालेज पिछली सरकार द्वारा खोले गए जिसकी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। प्रधानाचार्य एवम् मुख्याध्यापकों की नियुक्तियां भी हुईं, परन्तु अभी तक सैंकड़ों प्राथमिक पाठशालाएं, माध्यमिक पाठशालाएं तथा कालेज ऐसे हैं जहां पर अभी भी अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं जिससे छात्रों और छात्राओं के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके माता-पिता परेशान हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्यापक नहीं जा रहे हैं। यहां तक हो गया है कि जिन कालेजों को पिछली सरकार ने चालू करने की अनुमति दी थी, उनकी कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं की गई हैं। जिला शिमला में ठियोग में कालेज खोलने के लिए प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी हुई, परन्तु दुःख इस बात का है कि अभी तक भी वहां पर कालेज में कक्षाएं शुरू नहीं की गईं, जिससे लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है। लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद न किया जाए। राज्य सरकार को इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर राज्य सरकार के पास धन का अभाव है और वह इस बात में सक्षम नहीं है कि वह सारे अध्यापकों को वेतन दे सके तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि वह राज्य सरकार को इसके लिए आर्थिक सहायता दे। जो शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं वहां स्टाफ को भेजकर इस कठिनाई को दूर किया जाए।